

**ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND  
SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS  
THEREON**

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ  
**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO. 46**  
ANSWERED ON 07.02.2024

**Training of Panchayati Raj representatives**

**46 # Shri Mithlesh Kumar:**

Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state:

- (a) whether Government has taken any steps to train Panchayati Raj representatives in management leadership;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) the details of the MoU signed by the Ministry with IIM-A to train Panchayati Raj representatives, along with the objectives thereof?

**ANSWER**

**THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ**

**(SHRI GIRIRAJ SINGH)**

- (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 46 FOR ANSWER ON 07.02.2024 REGARDING TRAINING OF PANCHAYATI RAJ REPRESENTATIVES**

(a) & (b) Yes Sir. Centrally Sponsored Scheme of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) of the Ministry aims at developing Leadership and Governance capabilities at the grassroots through continuous capacity building activities of the Elected Representatives (ERs) and other Stakeholders of Panchayati Raj Institutions (PRIs). Towards this end, number of training programs are conducted by the National Institute for Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR), State Institute of Rural Development (SIRD) of States and other Training Institutions throughout the year. During last 10 years, including the current year, Ministry has implemented various schemes for Capacity Building & Training, including leadership training, for Elected Representatives and other stakeholders of Panchayati Raj Institutions through which total of 3,23,25,826 (3.23 cr.) participants were provided training to improve Panchayat Governance and leadership at the grassroots.

To further amplify the scope of the leadership training, the Ministry has recently formulated a Leadership/Management Development Program (MDP), a strategic initiative aimed at bolstering the leadership capabilities of Elected Representatives, officials and functionaries of Panchayati Raj Institutions (PRIs). The Program is designed to serve as a transformative tool in enriching the skill sets and knowledge base of the community leaders at the grassroot level.

The initiative envisages the collaboration between the States/UTs and the Apex Institutes/ Institutes of Excellence including Indian Institutes of Management (IIMs) / Indian Institutes of Technology (IITs) situated within their States/UT or in the vicinity through Memorandum of Understanding (MoU) for conducting Leadership/ Management Development Program. The detailed guidelines of the Leadership/ Management Development Program can be accessed on the Ministry's website.

(c) The Ministry has signed an MoU for collaboration with the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) on 8<sup>th</sup> January 2024. The MoU between Ministry of Panchayati Raj and IIMA, interalia, provided for conducting introductory Program under the Scheme of MDP, structure of the training, session plan and topics to be covered during the 5 days of training, indicative cost structure, logistic arrangements, etc. The pilot Leadership/Management Development Program for the Elected Representatives and Functionaries of Panchayati Raj Institutions was conducted at IIM Ahmedabad during January 15-19, 2024. Various topics including Leadership and Team work, Project Management, Financial Management, Creativity and Innovations, were covered during the training.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
पंचायती राज मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \* 46  
दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना

46 # श्री मिथलेश कुमार:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पंचायती राज के प्रतिनिधियों को प्रबंधन नेतृत्व में प्रशिक्षित करने के लिए कोई कदम उठाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा आईआईएम-ए के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और उसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री  
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 46 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) जी सर। मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थानों के अन्य हितधारकों की निरंतर क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर नेतृत्व और शासन क्षमताओं को विकसित करना है। इस दिशा में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर), राज्यों के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरे वर्ष कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चालू वर्ष सहित पिछले 10 वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थानों के अन्य हितधारकों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं, जिसके माध्यम से कुल 3,23,25,826 (3.23 करोड़) प्रतिभागीयों को पंचायत प्रशासन और जमीनी स्तर पर नेतृत्व में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

नेतृत्व प्रशिक्षण के दायरे को और बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में एक नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों की नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाना है। कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर समुदाय के नेताओं के कौशल सेट और ज्ञान आधार को समृद्ध करने में एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस पहल में नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में या आसपास स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम)/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) सहित शीर्ष संस्थानों/उत्कृष्ट संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सहयोग की परिकल्पना की गई है। नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

(ग) मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएमए) के साथ सहयोग के लिए 8 जनवरी 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय और आईआईएम, अहमदाबाद के बीच समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन विकास कार्यक्रम योजना के तहत परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित करने, प्रशिक्षण की संरचना, सत्र योजना और प्रशिक्षण के 5 दिनों के दौरान शामिल किए जाने वाले विषय, सांकेतिक लागत संरचना, लॉजिस्टिक व्यवस्था आदि शामिल हैं। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए पायलट नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम 15-19 जनवरी, 2024 के दौरान आईआईएम, अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान नेतृत्व और टीम कार्य, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, रचनात्मकता और नवाचार सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।

\*\*\*\*\*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, first supplementary.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, the Social Justice Department has limited spending on key schemes such as the SEED Scheme for De-notified Semi Nomadic and Nomadic tribes and the National Action Plan for Drug Demand Reduction. Similarly, the Tribal Department also is under-utilising funds in Eklavya Model Residential Schools and the PM Adi Adarsh Gram Yojana transfer. What measures has the Government implemented to identify and address the bottlenecks hindering the effective utilisation of these policies and funds given the increase in budgetary allocation for these schemes?

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :** सर, यह पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित प्रश्न नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary out of the remaining three; Shri Sandeep Kumar Pathak.

**श्री संदीप कुमार पाठक :** सर, आदिवासी भाइयों के अधिकारों, रीति-रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पेसा कानून को वर्ष 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत, इस कानून को अब तक लगभग दस राज्यों में लागू हो जाना चाहिए था। सर, लगभग 28 साल हो चुके हैं, यह कानून सिर्फ कागजों में ही है, अभी तक धरातल पर उतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासित कई राज्य भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि गुजरात। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 28 साल हो चुके हैं, लगभग दस साल पहले आपकी सरकार आ चुकी है, इसे धरातल पर उतरने में और कितना समय लगेगा?

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:** सर, यह प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है। अगर इन्हें पेसा की जानकारी चाहिए, तो वह अलग से दी जाएगी।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, sometimes, it appears to us that the answer is not forthcoming with respect to the supplementary. But we ignore one fact that the supplementary is not relatable to the Question and, therefore, the Minister is well within his rights that it is a good supplementary but it does not emanate from the Question which is before the House. Now, Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, the action by the Ministry to train the Panchayati Raj representatives in management leadership in one of the top-most management institutes of the country, which is the Indian Institute of Management, Ahmedabad, is really praiseworthy. My question is: Does the module include digital education to

these political representatives? On one hand, we are trying to increase the intensity of digital footprint in the rural areas and unless these representatives are educated and trained in handling these digital assets, they would not be able to exercise their management skills. Whether this forms a component of the entire leadership programme is a suggestion and if it is there, it is welcome step.

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" के माध्यम से पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 से लेकर 2014 तक 27 लाख प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन पिछले दस सालों में, 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 3,26,00,000 जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें जैसे ही जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, 6 महीने के अंदर उनको सामान्य अभिमुखीकरण का प्रशिक्षण, जैसे जनरल ओरिएंटेशन का प्रशिक्षण दिया जाता है, पुनश्चर्या कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी - टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमारी लगभग ढाई लाख पंचायतें गांव में जो विकास का प्लान करती हैं, उसे जीपीडीपी के माध्यम से अपलोड किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी पंचायतों ने निश्चित तौर पर आत्मसात कर ली है। मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति में कहते हैं - पंचायत से पार्लियामेंट तक, लेकिन हमारी पंचायतें अब 'पार्लियामेंट से पंचायत तक', इस तरह का टेक्नोलॉजी का काम करने जा रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट करती है, वहीं पर हमारी लगभग ढाई लाख पंचायतें भी पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट करने लगी हैं। सौ प्रतिशत पंचायतें ऑडिट ऑनलाइन करने लगी हैं। निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प की तरफ हमारी पंचायतें भी आगे बढ़ रही हैं। हमारी पंचायतें, चाहे वह गांव का डीपीआर बनाना हो, गांव की विकास योजना हो, गांव का डेवलपमेंट प्लान बनाना हो, इन सभी में टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ रही हैं।

**श्री सभापति:** इस सदन में कुछ सदस्य हैं, जिनका सफर पंचायत से शुरू हुआ और पार्लियामेंट तक पहुंचा। वर्तमान में भी ऐसे सदस्य हैं।

Now, Question No. 47, Dr. Ashok Kumar Mittal.